धरती बचाने के लिए काफी नहीं वैश्विक जलवायु वार्ता के नतीजे

डा. अरुणाभा घोष
सीईओ, काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर (सीइइडब्ल्यू)

वैश्विक वार्ता में जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने की बात की गई है लेकिन कोयले का उपयोग तेजी से कम करने पर जोर दिया गया। कोयला भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सभी जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने पर जोर दे रहा था। लेकिन तेल उत्पादक देशों के विरोध की वजह से ऐसा नहीं हो सका।

दुबई के 28वें जलवायु सम्मेलन में सभी के लिए कुछ न कुछ रहा। जलवायु वार्ताओं के 30 साल में पहली बार जीवाश्म ईंधन को छोड़ने पर हमारे पास स्पष्ट भाषा है, लेकिन इसमें कमियां हैं। इसके लिए जरूरी वित्त और प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कहां है या इसके लिए कौन भुगतान करेगा, इस पर स्पष्टता नहीं है। हाल के वर्षों में, भारत जलवायु वार्ताओं में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ-साथ सततशीलता के लिए कई कदम उठाए हैं। क्लाइमेट वनरेबल फोरम की हालिया रिपोर्ट ने भारत को उन चार देशों में शामिल किया है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पाने की राह पर हैं। लेकिन काप 28 अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी कदम उठाने में विफल रही। इसलिए जरूरी है कि इसका भारत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिहाज से विश्लेषण किया जाए। काप ने जीवाश्म ईंधन युग के अंत का संकेत दिया, लेकिन दूसरे ईंधन की तुलना में कोयले पर ज्यादा जोर रहा। पहले के काप में 'सभी जीवाश्म ईंधनों' को चरणबद्ध रूप से घटाने के भारत के प्रस्ताव को प्रतिध्वनि मिली थी, फिर भी ग्लोबल स्टाकटेक (जीएसटी) के समझौते में 'जीवाश्म ईंधनों' को चरणबद्ध रूप से घटाने' पर जोर देते हुए ज्यादा सतर्क रुख अपनाया गया है। हालांकि, तेल उत्पादक देशों की ताकत और प्रभाव के चलते 'तेजी से घटाने के लिए' कोयले को चुना गया, लेकिन तेल और गैस का कोई उल्लेख नहीं हुआ, जबकि कोयला भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

लेकिन, हम अक्षय ऊर्जा को तेजी से बढ़ाए बगैर जीवाश्म ईंधन को नहीं घटा सकते। एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में आप किसी कारखाने को बंद करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी बिजली कोयले से आती है। स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता, पवन और सौर क्षमता, में भारत पहले से दुनिया में चौथे स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा को और अधिक बढ़ाने के लिए, भारत ने वित्त और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया है। ग्लोबल साउथ को इनकी जरूरत है। दूसरा, अस्पष्टताओं के साथ लास एंड डैमेज फंड पर एक सकारात्मक शुरुआत हुई है। काप 28 के पहले दिन हानि व क्षति कोष के संचालन पर सहमति एक सकारात्मक प्रगति थी, लेकिन विकासशील देशों को सहायता देने के लिए अनिवार्य उत्तरदायित्व के अभाव और योगदान लक्ष्यों पर स्पष्टता की कमी ने चुनौतियां खड़ी कर दीं। भारत को जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले मौसमी बदलावों से लगातार हानि व क्षति उठानी पड़ रही है।